डाकघरों का कायाकल्प: एस्टेट प्रबंधन योजना का नया चरण

प्रकाशन: 26 नवंबर 2026

समाचार-संदर्भ: 25 नवंबर 2026 (केंद्रीय मंत्रिमंडल)

प्रिलिम्स: एस्टेट प्रबंधन योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, 16वाँ वित्त आयोग चक्र, सुगम्य भारत अभियान

मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-II/III, सार्वजनिक सेवा-वितरण, अवसंरचना, वित्तीय समावेशन



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com।

▼ इस लेख में

1. खबरों में क्यों
2. योजना क्या है
3. डाक नेटवर्क का पैमाना
4. आठ घटक, एक नज़र में
5. संबंधित अवधारणाएँ
6. परीक्षा की दृष्टि से विश्लेषण
7. आगे की राह
8. प्रिलिम्स परीक्षा: अभ्यास प्रश्न
9. मुख्य परीक्षा: अभ्यास प्रश्न
10. स्रोत
11. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

खबरों में क्यों

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **25 नवंबर 2026** को डाक विभाग की **एस्टेट प्रबंधन योजना (Estates Management Scheme)** को जारी रखने की मंज़ूरी दी। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना **16वें वित्त आयोग चक्र** में, यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक, चलेगी और इसका कुल परिव्यय **1,491 करोड़ रुपये** बताया गया है। [1]

योजना क्या है

> मूल बात समझिए: एस्टेट का अर्थ यहाँ डाक विभाग की अपनी ज़मीन, डाकघर की इमारतें और कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनियाँ हैं। जब कोई सेवा-विभाग किराये की इमारतों में चलता है तो उसे हर साल किराया देना पड़ता है और इमारत पर उसका नियंत्रण भी सीमित रहता है। यह योजना इसी ढाँचे को अपनी इमारतों, मरम्मत और एक जैसी पहचान (यूनिफ़ॉर्म ब्रांडिंग) के ज़रिए मज़बूत करने के लिए है।

उद्देश्य: सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार योजना डाक विभाग की एस्टेट-अवसंरचना का व्यापक आधुनिकीकरण करती है। इसमें डाकघरों और आवासीय कॉलोनियों का निर्माण, पुनर्निर्माण, नवीनीकरण और एक जैसी ब्रांडिंग तथा देश की धरोहर डाक-इमारतों का संरक्षण शामिल है।

किससे जुड़ती है: विज्ञप्ति इसे पहली-मील (first-mile) डिलीवरी, वित्तीय समावेशन और नागरिक-केंद्रित सेवा से जोड़ती है। साथ ही इसे डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप बताया गया है।

डाक नेटवर्क का पैमाना

विज्ञप्ति के अनुसार भारत में **1.65 लाख डाकघर** हैं, जिनमें **1,49,385 ग्रामीण क्षेत्रों** में हैं। यानी करीब 90 प्रतिशत डाकघर गाँवों में हैं। ये डाकघर केवल चिट्ठी-पार्सल तक सीमित नहीं हैं। इनसे डाकघर बचत बैंक (POSB), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), डाक जीवन बीमा (PLI), आधार सेवाएँ, पोस्ट ऑफ़िस पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकघर निर्यात केंद्र (DNK) के ज़रिए ग्रामीण कारीगरों को सहायता जैसी सेवाएँ भी मिलती हैं।

इसी कारण इमारतें यहाँ केवल ईंट-गारे का मामला नहीं हैं। दूर-दराज़ के गाँव में सुरक्षित, सुलभ और पहचानने योग्य डाकघर ही उन सेवाओं का पहला संपर्क-बिंदु बनता है।

आठ घटक, एक नज़र में

विज्ञप्ति में योजना के घटक इस प्रकार दिए गए हैं (राशि करोड़ रुपये में):

घटक	क्या होगा	राशि
नया निर्माण	रिक्त विभागीय भूखंडों पर 190 विभागीय डाक-इमारतें, ताकि किराये के स्थान हटें और किराये की देनदारी घटे	280
पुनर्निर्माण	50 जर्जर विभागीय इमारतों को तोड़कर दोबारा बनाना	108
नवीनीकरण और ब्रांडिंग	2,550 विभागीय उप-डाकघरों में सुधार और एक जैसी ब्रांडिंग	318
किराये के डाकघरों का उन्नयन	किराये की इमारतों में चल रहे 2,500 डाकघरों का उन्नयन और ब्रांडिंग	37.50

घटक	क्या होगा	राशि
धरोहर संरक्षण	20 प्रमुख धरोहर डाक-इमारतों की मरम्मत और संरक्षण	180
कॉलोनी नवीनीकरण	अधिक माँग वाली 150 डाक आवासीय कॉलोनियों का कायाकल्प	357.50
सहायक और समावेशी कार्य	सौर ऊर्जा, वर्षा-जल संचयन, रैंप और ब्रेल संकेतक (सुगम्य भारत अभियान के तहत), महिला शौचालय और शिशु-आहार कक्ष	100
एकीकृत प्रौद्योगिकी केंद्र	बेंगलुरु में डाक प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र (CEPT) के लिए स्थायी भवन, उन्नत डाक प्रौद्योगिकी सेवाओं और स्वदेशी ओपनसोर्स टेक स्टैक के समर्थन हेतु	100

ध्यान दें: विज्ञप्ति में कुल परिव्यय 1,491 करोड़ रुपये है, जबकि ऊपर दिए आठ घटकों की राशि जोड़ने पर 1,481 करोड़ रुपये बनते हैं। 10 करोड़ रुपये का यह अंतर विज्ञप्ति में स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए परीक्षा में कुल परिव्यय के रूप में आधिकारिक आँकड़ा 1,491 करोड़ रुपये ही लिखिए और घटक-वार राशियाँ विज्ञप्ति के अनुसार पढ़िए।

संबंधित अवधारणाएँ

केंद्रीय क्षेत्र की योजना: ऐसी योजना जिसे केंद्र सरकार की ओर से पूरी तरह वित्त-पोषित और केंद्रीय विभाग द्वारा लागू किया जाता है। यहाँ यह डाक विभाग (संचार मंत्रालय) की योजना है।

वित्त आयोग चक्र: हर वित्त आयोग की सिफ़ारिशें एक निश्चित अवधि (आम तौर पर पाँच वर्ष) के लिए होती हैं। योजनाओं को उस चक्र के हिसाब से जारी रखने की मंज़ूरी ली जाती है। यहाँ चक्र 2026-27 से 2030-31 का है।

पहली-मील डिलीवरी: सेवा या पार्सल के नेटवर्क में शुरुआती बिंदु पर, यानी उपभोक्ता के सबसे नज़दीकी स्थान पर, मिलने वाली पहुँच।

सुगम्य भारत अभियान: दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक भवनों, परिवहन और सूचना को सुलभ बनाने का राष्ट्रीय अभियान (Accessible India Campaign)। यहाँ रैंप और ब्रेल संकेतक इसी के अनुरूप बताए गए हैं।

इसी दिन की एक और मंज़ूरी: उसी दिन मंत्रिमंडल ने डाक विभाग की एक अलग केंद्रीय योजना, डाक संचालन योजना, को भी जारी रखने को मंज़ूरी दी। दोनों योजनाएँ अलग हैं, एस्टेट योजना इमारतों और बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित है।

परीक्षा की दृष्टि से विश्लेषण

किराये से स्वामित्व की ओर: 190 नई इमारतें किराये की जगहों को हटाने के लिए हैं। इससे किराये की देनदारी घटती है, पर यह लाभ तभी मिलेगा जब इमारतें समय पर और गुणवत्ता से बनें।

समावेशन का पहलू: रैंप, ब्रेल संकेतक, महिला शौचालय और शिशु-आहार कक्ष योजना को केवल इमारत-निर्माण से आगे ले जाते हैं। इससे डाकघर दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए अधिक सुलभ बनते हैं।

धरोहर और पर्यावरण: 20 धरोहर इमारतों का संरक्षण और सौर ऊर्जा तथा वर्षा-जल संचयन जैसी सुविधाएँ विरासत और सतत विकास, दोनों को जोड़ती हैं।

सीमाएँ: विज्ञप्ति में प्रदर्शन-सूचक (जैसे किराया कितना घटेगा, कितने डाकघर कब तक पूरे होंगे) नहीं दिए गए हैं। साथ ही कुल परिव्यय और घटक-योग का 10 करोड़ रुपये का अंतर स्पष्ट नहीं है। इसलिए योजना के वास्तविक असर का मूल्यांकन क्रियान्वयन-आँकड़े आने पर ही संभव होगा।

आगे की राह

योजना की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि निर्माण और नवीनीकरण का काम तय समय में पूरा हो, बनी इमारतों का रखरखाव चलता रहे और सुगम्यता के प्रावधान वास्तव में उपयोग में आएँ। साथ ही, इमारतों के सुधार को डाकघर की सेवाओं की गुणवत्ता से जोड़कर देखा जाना चाहिए, जैसे बैंकिंग और बीमा सेवाओं की पहुँच तथा ग्रामीण डाकघरों में प्रतीक्षा-समय। परिणाम-आधारित सार्वजनिक रिपोर्टिंग से यह जवाबदेही बढ़ेगी।

प्रिलिम्स परीक्षा: अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. डाक विभाग की एस्टेट प्रबंधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 16वें वित्त आयोग चक्र में वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखा गया है।

कथन 2: इसके अंतर्गत रिक्त विभागीय भूखंडों पर 190 नई डाक-इमारतें बनाने का प्रावधान है, ताकि किराये के स्थान हटाए जा सकें।

कथन 3: इसमें प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र (CEPT) के लिए स्थायी भवन हैदराबाद में बनाने का प्रावधान है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a)

कथन 1 सही है, योजना केंद्रीय क्षेत्र की है और 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। कथन 2 सही है, 190 नई इमारतें रिक्त विभागीय भूखंडों पर बनेंगी। कथन 3 गलत है, CEPT के लिए स्थायी भवन बेंगलुरु में प्रस्तावित है, हैदराबाद में नहीं।

प्रश्न 2. एस्टेट प्रबंधन योजना के घटकों में सबसे अधिक राशि किसके लिए निर्धारित है?

(a) नया निर्माण
(b) विभागीय उप-डाकघरों का नवीनीकरण और ब्रांडिंग
(c) डाक आवासीय कॉलोनियों का नवीनीकरण
(d) धरोहर डाक-इमारतों का संरक्षण

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c)

विज्ञप्ति के अनुसार डाक आवासीय कॉलोनियों के नवीनीकरण के लिए 357.50 करोड़ रुपये हैं, जो घटकों में सबसे अधिक है। नवीनीकरण और ब्रांडिंग के लिए 318, नया निर्माण के लिए 280 और धरोहर संरक्षण के लिए 180 करोड़ रुपये हैं।

मुख्य परीक्षा: अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. "डाक विभाग की एस्टेट प्रबंधन योजना केवल इमारतों के निर्माण की योजना नहीं, बल्कि सेवा-वितरण और समावेशन का साधन है।" चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

> **भूमिका में:** योजना की मंज़ूरी, अवधि और परिव्यय का संक्षिप्त परिचय; डाक नेटवर्क के पैमाने का उल्लेख।

> **मुख्य भाग में:** किराये की इमारतों से अपनी इमारतों की ओर बढ़ना; जर्जर इमारतों का पुनर्निर्माण; एक जैसी ब्रांडिंग; सुगम्यता और महिला-अनुकूल सुविधाएँ; धरोहर संरक्षण; सौर ऊर्जा और वर्षा-जल संचयन; CEPT का स्थायी भवन; सीमाएँ, जैसे प्रदर्शन-सूचकों का अभाव और क्रियान्वयन की चुनौतियाँ।

> **निष्कर्ष में:** संतुलित निष्कर्ष: इमारतें सेवा की नींव हैं, पर असली मूल्यांकन ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता और पहुँच से होगा।

स्रोत

- [1] https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2341181&lang=2&reg=48

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

▼ एस्टेट प्रबंधन योजना को कब तक जारी रखा गया है?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2026 को इसे 16वें वित्त आयोग चक्र में, यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक, जारी रखने की मंज़ूरी दी।

▼ योजना का कुल परिव्यय कितना है?

विज्ञप्ति के अनुसार पाँच वर्ष में कुल परिव्यय 1,491 करोड़ रुपये है। विज्ञप्ति में दिए घटक-वार आँकड़ों का योग 1,481 करोड़ रुपये बनता है, इस अंतर की व्याख्या नहीं दी गई है।

▼ इस योजना में कितनी नई इमारतें बनेंगी?

रिक्त विभागीय भूखंडों पर 190 नई डाक-इमारतें बनाने का प्रावधान है, साथ ही 50 जर्जर इमारतों का पुनर्निर्माण भी होगा।

▼ यह डाक संचालन योजना से कैसे अलग है?

एस्टेट प्रबंधन योजना इमारतों और आवासीय कॉलोनियों जैसे भौतिक ढाँचे पर केंद्रित है, जबकि डाक संचालन योजना डाक विभाग की एक अलग केंद्रीय योजना है, जिसे उसी दिन मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी।